

भारत बंद के चलते राजस्थान में हाई अलर्ट

चर्चा में क्यों?

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित भारत बंद के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट है।

यह वरिध प्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालय के उस नरिणय के वरिध में है, जसिमें राज्यों को अनुसूचति जातयिों (SC) और अनुसूचति जनजातयिों (ST) के बीच 'करीमी लेयर' की पहचान करने तथा उन्हें आरक्षण लाभ से बाहर करने का नरिदेश दयिा गया है।

मुख्य बदि

- सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया किराज्यों को पछिडेपन के वभिनिन स्तरों के आधार पर SC और ST को उप-वर्गीकृत करने की संवैधानकि अनुमति है।
- सात न्यायाधीशों की पीठ ने नरिणय सुनाया किराज्य अब सबसे वंचति समूहों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लयि 15% आरक्षण कोटे के भीतर SC को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया है कि 'करीमी लेयर' सदिधांत, जो पहले केवल अन्य पछिडा वर्ग (OBC) पर लागू होता था (जैसा कि इंदरा साहनी मामले में उजागर कयिा गया था), अब SC और ST पर भी लागू होना चाहयि।
- इसका अर्थ है किराज्यों को SC और ST के भीतर करीमी लेयर की पहचान करनी चाहयि तथा उन्हें आरक्षण लाभों से बाहर करना चाहयि।

बंद, हडताल या इसी तरह के वरिध प्रदर्शन आयोजति करने की संवैधानकिता

- भारतीय संवधिान का अनुच्छेद 19(1)(c) नागरकिों को संघ या यूनयिन बनाने का मौलकि अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 19 अपने नागरकिों के अधिकारों, वशिष रूप से भाषण और अभवियक्ती की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में राज्य की शक्ति को प्रतबिधति करता है।
- अनुच्छेद 19(1)(a) नागरकिों को भाषण और अभवियक्ती की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जसिमें वभिनिन माध्यमों से राय, वशिवास एवं दृढ़ वशिवास व्यक्त करना शामिल है।
 - वचिरों के प्रत्यक्ष प्रतनिधितिव के रूप में प्रदर्शनों को अभवियक्ती की स्वतंत्रता के तहत संरक्षति कयिा जाता है, बशरते वे अहसिक और व्यवस्थति हों।
 - हडतालों को अभवियक्ती की स्वतंत्रता के दायरे में शामिल नहीं कयिा गया है।
- अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से नागरकिों को हडताल, बंद या चक्का जाम आयोजति करने का मौलकि अधिकार नहीं देता है।